

इकाई 9 कृषि भूमि और भू-सम्पत्ति अधिकार आन्दोलन

इकाई की रूपरेखा

- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 कृषि भूमि संरचना
 - 9.2.1 औपनिवेशिक संरचना
 - 9.2.2 बदलती हुई परम्पराएँ
- 9.3 कृषि भूमि सम्बंधी सुधार
 - 9.3.1 संरचनात्मक सुधार
 - 9.3.2 उदारतावादी सुधार
- 9.4 किसान और भूमि सम्बंधी अधिकार आन्दोलन
 - 9.4.1 मैक्सिको में इमीलियानों ज़पाटा का आन्दोलन
 - 9.4.2 मोवीमेंटो सेम टेरा (एम एस टी)
- 9.5 सारांश
- 9.6 अभ्यास प्रश्न

9.1 प्रस्तावना

लैटिन अमेरिका में कृषि भूमि और भूमि अधिकार आन्दोलन का आरंभ औपनिवेशिक के समय से पहले ही आरंभ हो चुका था। औपनिवेशिक काल के दौरान देशज विद्रोही और दास, बगावत के साथ ही किसान आन्दोलन आरंभ हुआ। यद्यपि, औपनिवेशिक इस आन्दोलन की गति की मात्रा को हानि पहुँचाने का कारण नहीं बना। कृषि भूमि सम्बंधी संरचना परम्परागत से अनुचित और अन्यायपूर्ण थी, ठीक से भूमि सुधार के सम्बंध में संगठन की कमी तथा प्रेरणा का अभाव रहा है। इसके बाद आर्थिक उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया द्वारा इस प्रेरणा को समर्थन मिला, साथ ही आज के ग्रामीण गरीबों में असंतोष की लहर उभर कर सामने आई और भूमि सुधार प्रमुख मुद्दा बना।

इन आन्दोलनों ने अनेक रूप धारण किए अथवा यह कह सकते हैं कि यह विभिन्न प्रकार से आन्दोलित हुआ, सामाजिक दस्युता उग्रवाद के बीच में फंस गया और किसानों की क्रान्ति ने हिंसा का रूप धारण कर लिया। जबकि कुछ देशों ने किसान आन्दोलनकर्ताओं को आश्वासन दिया कि उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा और उस पर कार्यवाही की जाएगी। कुछ देशों ने मामूली औपचारिकता ही निभाई जिसका कोई व्यावहारिक व सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार के आन्दोलनों का विपरीत प्रभाव इसका उदाहरण है। मैक्सिको में हुए इमीलियानो (Emiliano) ज़पाटा आन्दोलन का यहाँ जिक्र किया जा सकता है जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि भूमि सम्बंधी सुधार करना था, ब्राज़ील की *मूवीमेंटो सेम टेरा (Movimento Sem Terra - MST)* और कोलाम्बिया में राजनीतिक अभिप्रेरणा से ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा की गई जिससे अनेक लोगों की जाने गई।

इस इकाई में भूमिहीनों और ग्रामीण गरीबों के द्वारा पूरे लैटिन अमेरिका में किए गए आन्दोलन का विश्लेषण किया गया है। इस प्रक्रिया में, हम लैटिन अमेरिका में परम्परा कृषि सम्बंधी संरचना का अध्ययन करेंगे और भूमि सुधारों पर किए गए प्रयासों पर विहंगम दृष्टि डालेंगे तथा इस बात का प्रयास करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि आज यह आन्दोलन फिर से क्यों उभर रहा है।

9.2 कृषि भूमि संरचना

कृषि भूमि संरचना संस्थाओं के समूह अथवा अधिशासी मानकों की सीमाओं के अन्तर्गत समाविष्ट है तथा भूमि की गहनता का उत्पादन स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है। लैटिन अमेरिका के देशों में भूमि संरचना की जड़ें स्पेन या पुर्तगाली औपनिवेशिक इतिहास में मौजूद हैं, जिनका विकास सैकड़ों वर्षों में हुआ है।

कृषि भूमि संरचना का विकास मूल रूप से साम्प्रदायिकता की अवधि में हुआ है जो औपनिवेशिक काल से भी पहले का है, उस समय मेसो अमरीका (Meso America) में एज़टेक्स (Aztecs) और एंडेज में इनकास (Incas) सम्प्रदाय प्रचलित थे। कृषि भूमि संरचना का मूल स्वरूप साम्प्रदायिक भूमि पट्टेदारी में था जो आज भी संशोधित स्वरूप में मौजूद है। परन्तु भूमि को सावधिकता के आधार पर उसके सदस्यों में वितरित कर दिया जाता था और परिवार के अनुसार उसके नाम या शीर्षकों में परिवर्तन कर दिया जाता था। इसके अतिरिक्त कृषियोग्य भूमि को सामान्य भूमि माना जाता था जिस पर प्रत्येक व्यक्ति समूहों के आधार पर अपना कब्ज़ा बना लेता था। ये स्वरूप मूलरूप से साम्प्रदायिकता के आधार पर विभाजित था और इसीलिए बहुत सारी कृषि योग्य भूमि राजा अथवा सम्राट के पास होती थी जिसपर आम किसान यह समझा कर कृषि करते थे कि वे राजा की सेवा में यह सब कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रागैतिहासिक काल की समाजों में भी कुलीन लोगों या शक्तिशाली लोग ही भूमि के मालिक होते थे।

9.2.1 औपनिवेशिक संरचना

अमेरिका की विजय होने पर इस भूमि पर क्राउन यानि की सम्राट के नाम पर कृषि की जाने लगी किन्तु वास्तव में महत्वपूर्ण व्यापारिक हितों के आधार पर श्रृंखलाबद्ध निजी अंशदाताओं ने कृषि करना आरंभ किया जिसमें राज्य की भागीदारी निश्चित की गई थी। केवल इसके बाद सेना की विजय प्राप्ति से और सेना के शासन के दौरान भूमि पर सक्रिय रूप से सम्राट की भूमिका आरंभ हुई। और उस समय सम्राट ने कृषि नीति का विकास किया। ये नीतियाँ निम्न प्रकार से प्रतिपादित की गईं:

1) सैनिकों को भूमि दी जाए जो युद्ध और विजय में भागीदार थे। भूमि अनुदान की व्यवस्था को स्थापित किया (haciendas, estancias) इनकोमींदास (Encomiendas) जहाँ पर विजेता को यह अधिकार था कि वह बिना किसी कृषि भूमि के वह देशज कृषकों से उपहार तथा सेवाएँ प्राप्त कर सकता था, इस नियम की भी स्थापना की गई थी। यह देशज सामाजिक संरचना के मूल तत्वों, और सामाजिक संक्रमण एवं ईसाई धर्म की शिक्षा के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण करने का प्रयास था। सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सुधार आरंभ हो गए थे जबकि वास्तव में भूमि का नियंत्रण और कब्ज़े पहले से ही इनकोमींदा के आधार पर निजी सम्पत्ति के अंतर्गत स्थापित कर दिए गए थे। देशी लोगों के लिए भूमि की निर्वाह पद्धति को रद्द कर दिया गया था वहीं पर भूमि और वहाँ पर जनसंख्या सम्राट की सम्पत्ति मानी गई थी। *रीपाटीमेंटो (Repartimiento)* के तहत देशी लोगों के श्रमिक के रूप में आरोपित किया या यह कह सकते हैं कि उन्हें भूमि में खेतिहर मज़दूरों का दर्ज़ा दिया गया था।

2) उष्णकटिबंधी और उप-उष्णकटिबंधी बागानों का संगठन। (बाद में इन्हें अन्य निर्यात फसलों में शामिल कर लिया गया था)। कुछ वर्षों के बाद लैटिन अमेरिका ने बाज़ार में विक्रय योग्य फसलों की श्रृंखला का आरंभ करके आर्थिक चक्र की श्रृंखला की शुरुआत की थी विभिन्न देशों में आपूर्ति के लिए ये फसलें थी जैसे कि कोको, कॉफी, कपास, केले और गेहूँ इत्यादि। इन उत्पादों की अधिकतर फसल पैदा करने के लिए लगातार श्रमिकों की आवश्यकता महसूस की

जाती थी। जब देशज लोगों को इस श्रम के लिए दास बनाने के प्रयास में असफल रहने के बाद, इसके विकल्प के लिए अफ्रीका के गुलामों का आयात करना पड़ा था क्योंकि समुद्रतटीय क्षेत्रों की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए उष्णकटिबंधी बागानों पर काम करने के लिए श्रमिक मूल आधारित आवश्यकता बन गए थे। इस प्रथा या नियम कानूनों को उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग सभी देशों ने रद्द कर दिया था।

बागान फसलें (कुछ विशेष क्षेत्रों में ही सिमट कर रह गई थी तथा द्वीपों, साइबेरिया के तटवर्ती क्षेत्र, ब्राज़ील के उत्तरपूर्वी तथा पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण अमेरिका के भीतरी क्षेत्रों से अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। कृषि से सम्बंधित वस्तुओं को तटीय क्षेत्रों से दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए परिवहन की विकट समस्या खड़ी हो गई थी।

- 3). *खनन क्षेत्रों और शहरी केन्द्रों में खाद्य आपूर्ति के लिए प्रावधान का निर्माण।* लैटिन अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि बहुत ऊँची दर पर थी वहीं पर ही शहरीकरण की दर भी इसी तरह से बढ़ी हुई थी। दोनों के कारण खाद्य उत्पादों की माँग में अत्यधिक वृद्धि हुई इस तरह से जनसंख्या के अनुपात में खाद्य आपूर्ति का अनुपात बहुत कम था।

जमींदारों व अभिजात वर्गों और स्पेन के प्रशासन के बीच कृषि मामलों पर संघर्ष और भयानक प्रतिरोध था। सम्राट यानि क्राउन ने स्पेन के कृषकों को कुछ पूर्ण स्वामित्व भूमि का ग्रामीण बन्दोबस्त करके और इसी प्रकार देशी समुदायों को इसमें शामिल करके जमींदार वर्ग को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया था किन्तु उसके ऐसा करने से कोई लाभ नहीं हुआ। वास्तव में इस सामाजिक संरचना को *लैटीफुंडिया (latifundia)* द्वारा शासित किया जा रहा था, वे ही इसके प्रमुख थे। इसके साथ ही लोक अधिकारियों सहित प्रत्येक व्यक्ति व्यावहारिक रूप से भूमि धारकों पर निर्भर करते थे।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक, सबसे बड़ा एक मात्र भूमिधारक चर्च ही था उस समय के बुर्जुआ प्रयास कर रहे थे भूमि मुक्त बाज़ार में आ जाए, इसका सीधा सा परिणाम यह था कि ग्रामीण मध्य वर्ग के उत्थान से नेतृत्व परिवर्तन के स्थान पर भूमि को निजी हाथों में केन्द्रीकृत कर दिया जाए यही उनका प्रमुख उद्देश्य था। इसका अन्तः मूलस्रोत लैटिन अमेरिका के कृषि संरचना में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार से आरंभ हो गया था। उदाहरण के लिए ब्राज़ील में दासों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके परिणामस्वरूप समग्र यूरोप (पुर्तगाल, जर्मन, इटली) और जापान के कृषकों के व्यापक योगदान से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। इसके साथ ही अर्जेन्टीना और ऊरुग्वे जैसे देशों में पशु अर्थव्यवस्था को किस्तार मिला जिससे विभिन्न स्थितियों के लिए श्रमिकों की माँग में कमी आई अथवा यह कह सकते हैं कि श्रमिकों के स्थान पर अब पशुओं से काम लिया जाने लगा था।

9.2.2 बदलती हुई परम्पराएँ

प्रौद्योगिकी का विकास सुधार के लिए निरसंदेह अत्यंत आवश्यक है। लैटिन अमेरिका में हमें दो विपरीत तत्व दृष्टिगोचर होते दिखाई दे रहे थे। एक तरफ, वहाँ पर उपजाऊ भूमि, श्रमिक, परिवहन स्थितियाँ जहाँ पर आधुनिक पूँजीपति उद्यमों उत्पादन की व्यवस्थित यान्त्रिकी इकाइयाँ स्थापित कर रहे थे और बाज़ार में शहरी माँगों के अनुसार चीनी, कपास, चावल, शीशम, माँस डेयरी उत्पादों की भरपूर आपूर्ति कर रहे थे और उत्पादकता की ऊँची दरों को छू रहे थे। परन्तु दूसरी ओर, छोटी जोत के किसान, काश्तकार खेतिहर मज़दूर, सेवाधिकारियों के किसी भी तरह के विकास के चिह्न मुश्किल से दिखाई देते हैं, इसके उदाहरण न के बराबर हैं। इसलिए व्यापक रूप से कहा जा सकता है कि लैटिन अमेरिका के देशों में खाद्य की बढ़ती हुई माँग की आपूर्ति को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र में

समुचित सुधार दिखाई नहीं देता था। इसका प्रमुख कारण परम्परागत कृषि संरचना का संकेन्द्रीयकरण है अथवा परम्परागत साधनों के माध्यम से कृषि कार्य पूरे किए जाते थे।

यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि लैटिन अमेरिका की कृषि संरचना व्यापक रूप से लाटीफुंडिया पर केन्द्रित है जिनके पास अधिकार भूमि है, और एक बड़ी किसान जनसंख्या जो मिनीफुंडिया (भूमि की बहुत ही छोटी इकाइयाँ जो एक परिवार का भी पालन करने में सक्षम नहीं हैं) की उत्तरजीवितता की आवश्यकता की पूर्ति करती है। यहाँ तक की मिनीफुंडिया परिचालक अंशकालिक रोजगार पर निर्भर करते हैं।

भूमि परम्परागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सम्पत्ति का प्रमुख स्रोत है। परन्तु लाटीफुंडिया और मिनीफुंडिया दोनों ही संसाधनों का उपयोग बहुत ही बुरी तरह से करते हैं। भूमि कम होती है और उसका गहन कृषि के लिए बेहद भूमि का उपयोग किया जाता है कारण स्पष्ट है छोटी भूमि धारकों का मुख्य उद्देश्य सबसे पहले अपना जीवनयापन करना है अर्थात् पहले अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैदावार करनी होती है। अधिक भूमिधारकों के पास या व्यापक सम्पत्तियों में अच्छी प्रौद्योगिकी, पूँजी निवेश और प्रारंभिक स्तर उनका ऊँचे स्तर की प्रबंधन व्यवस्था होती है। उनके उत्पादन का स्तर ऊँचा होता है जिसका निर्धारण श्रमिकों के इस्तेमाल पर निर्भर होता है। इसका कारण जमींदार है जो आर्थिक शक्ति को अपने पास बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि वे किसानों को कमजोर स्थितियों में बनाए रखना चाहते हैं साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि वे असुरक्षित रहें। इसलिए ये काश्तकारी संस्थाएँ आर्थिक और सामाजिक विकास को बनाए रखने में और मौजूदा असमानताओं को बनाए रखने के लिए उन्हें वैध बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए वे बाधा डालने अथवा रुकावट पैदा करने के उद्देश्य से भूमि, श्रमिक बल और आर्थिक उत्पादकता का सक्षम व भरपूर प्रयोग करते हैं।

अतः कृषि में परिवर्तन और प्रौद्योगिकी नवीनीकरण करने का प्रयास किया गया है किन्तु व्यवस्था की परम्परागत विशेषताओं के विकल्प का भरपूर प्रयोग और उपयोग नहीं किया गया है। कृषि सम्बंधी धरोहर का प्रकटीकरण इस प्रकार है: भूमिधारियों का लीटीफुंडिया - मिनीफुंडिया ढाँचा है, ग्रामीण वर्णीय समाज मालिक और अर्ध मालिक के रूप में बंटी हुई है पीनाज, दूध काश्तकारी असुरक्षा तथा गतिशीलता की कमियों में विभाजित है। सम्पत्ति तथा प्राकृतिक संसाधनों का केन्द्रीयकरण के साथ गरीबी का गठजोड़ बना हुआ है। यह वास्तव में भूमि काश्तकारी व्यवस्था के कारण असमानता है जो लैटिन अमेरिका में विकास को बाधित करने में एक प्रमुख रुकावट है।

9.3 कृषि भूमि सम्बंधी सुधार

लैटिन अमेरिका के देशों में भूमि सम्बंधी सुधार मुख्य रूप से असंतोषजनक भूमि सम्बंधी पट्टेदारी स्थिति सम-सामन्तवादी अथवा जागीरदारी कृषि संरचना है जिसका आरंभ औपनिवेशिक काल से हुआ है। किसी भी कृषि भूमि सम्बंधी सुधार का मुख्य सिद्धान्त भूमि सम्बंधी संसाधनों का पुनःवितरण होता है। कृषि भूमि सम्बंधी सुधार बहुत पुराना पड़ चुका कृषि भूमि संरचना को सुधारने का प्रश्न नहीं है। बल्कि यह कृषि भूमि सुधार नीतियों को आगे बढ़ाने का है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास एवं नवीन भूमि संरचना द्वारा उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए देश की आवश्यकताओं के प्रावधानों का समाविष्ट दस्तावेज़ तैयार होना चाहिए। भूमि का मात्र वितरण सभी समस्याओं का उत्तर नहीं है परन्तु कृषि भूमि सम्बंधी संरचना का एक प्रश्न है जो कि देश की समुचित कृषि विकास के केन्द्र बिन्दु पर आधारित होनी चाहिए। कृषि भूमि सम्बंधी सुधार ने हाल के दशकों में नाटकीय रूप से पलटा खाया है। मैक्सिको में कारडेनास के अन्तर्गत 1930 के दशक का मूल भूमि सम्बंधी सुधार से लेकर 1980 के दशक में हुए निकारागुआ में सैंडीनिस्टा (sandinista) में भूमि सम्बंधी सुधारों

का मुख्य मुद्दा यह था कि राज्य भूमि सम्बंधी संसाधनों का वितरण करने के लिए संगठित रूप से प्रयास करें और उन्हें लागू करें। यह संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के आधार पर टिका था जिसमें राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका शामिल थी। अभी हाल के कुछ सुधार उदारवादी प्रकृति के हैं तथा भूमि संसाधनों का पुनःवितरण और अधिक बाज़ार मूलक है।

लैटिन अमेरिका में पहला कृषि भूमि सम्बंधी सुधार 1910 की क्रान्ति के बाद मैक्सिको में आरंभ हुआ। गोटेमाला ने 1944 में इन सुधारों को अग्रेसित किया (जो 1954 तक पूरे नहीं हुए थे), और बोलीविया में इन सुधारों को 1952 की क्रान्ति के बाद लागू किया था। क्यूबा की क्रान्ति के साथ ही 1950 के दशक के उत्तरार्द्ध में लैटिन अमेरिका में अग्रेसित भूमि सम्बंधी सुधार आरंभ हुए थे। जबकि क्यूबा की क्रान्ति से पहले भूमि सम्बंधी सुधार आसानी से सम्पन्न हो रहे थे जिसमें राजनीति का अप्रत्यक्ष प्रभाव इसके साथ दृष्टिगोचर होता है। क्यूबा की क्रान्ति से सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान किसान आन्दोलन की ओर जाने लगा था तथा इसमें व्यापक जन विशेष रूप से लोग शामिल हुए थे। भयभीत अमरीका लैटिन अमेरिका के अधिकतर देशों को इस बात के लिए राजी कर रहा था कि अन्याय पूर्ण संरचना तथा भूमि काश्तकारी व्यवस्था को बदलने के लिए व्यापक कृषि भूमि सम्बंधी सुधारों के कार्यक्रमों को उत्साहित करें और उन्हें लागू करने में अपना सहयोग प्रदान करें। इसका उद्देश्य भूमि को काश्तकारी और उसके प्रयोग को न्यायसंगत बनाने के लिए परम्परागत लाटीफुंडिया और छोटे-क्षेत्रों की जोतों को बदलना था ताकि लोगों को भूमि उपलब्ध कराई जा सके जो इस पर काम करते हैं और "वे स्वतंत्रता और अस्मिता या प्रतिष्ठा की प्रतिभूति को प्राप्त कर सकें" (पुंटा डेल इस्ते का घोषणापत्र)। इसका परिणाम यह हुआ कि भूमि सम्बंधी सुधारों के लिए कानूनों की एक श्रृंखला बनी और जिनके पास समुचित भूमि नहीं थी उनके सहित किसानों और लोगों को भूमि देने के लिए कृषि भूमि सम्बंधी सुधार संस्थाओं और परियोजनाओं का नियोजन करने के लिए संगठनों का विधिवत निर्माण किया गया। इसके परिणामस्वरूप कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों में शक्ति संरचना में परिवर्तन का लक्ष्य रखने के साथ किसानों के कल्याण के लिए सारवान सुधारों को लागू किया जा सके। इन सबमें कृषि भूमि सम्बंधी सुधारों के प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे।

अन्ततः अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिषद के अनुसार कृषि भूमि सम्बंधी सुधारों के माध्यम से प्रभावी संरचना में परिवर्तन करना नितांत आवश्यक था तथा सम्बंधित क्षेत्र के लिए विकास हेतु मूल आवश्यकताएँ हैं इस भूमि काश्तकारी की संरचना में परिवर्तन करने से सट्टाबाज़ारी और आर्थिक प्राधिकारिता के स्रोतों को रोकना था जो सुधारों में भारी अड़चन पैदा करते थे। इसके साथ ही किसानों के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा किसानों को नीतिगत निर्णयों एवं राजनीति में भागीदारी आर्थिक और सामाजिक अवसरों को उपलब्ध कराने के माध्यम से शक्ति संरचना में सुधार करना था।

लैटिन अमेरिका में इस भूमि सुधार आन्दोलन को सफल होने में इतना लम्बा समय क्यों लगा है? इसका उत्तर उपर्युक्त बताए गए भूमि सम्बंधी सुधारों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से उपाय नहीं किए गए थे। जिसके परिणामस्वरूप इस आदर्श से दूर रहा - भूमि और सम्पत्ति का असमान वितरण, ग्रामीण जनता के लिए दोगम दर्ज़े का जीवन स्तर किसानों के नए कृषि क्षेत्र घटिया थे। इसलिए यह सबको सफलता प्राप्त नहीं हुई। नीतियों, व्यवहारों का निर्माण किया गया था वह व्यर्थ था क्योंकि उन्हें लागू नहीं किया गया था वहीं पर वे लागू करने में असमर्थ रहे। इसको प्रति सुधार या सुधारों के विपरीत कार्य करने के नाम से जाना जाता है। यह आन्दोलन नहीं था, और न ही कृषि भूमि सम्बंधी सुधारों की तरह से सूत्रबद्ध कार्यक्रम था। यह एक नीति थी परन्तु यह कार्यक्रम नहीं था और न ही यह औपचारिक था। इसका अभिकर्ता तो था, किन्तु अभिकरण नहीं था और असंगठित तथा गुमनाम था। प्रति सुधार करने वाली शक्तियाँ इस प्रयास में थी कि पूर्व स्थिति बनी रहे जबकि कृषि भूमि सुधारक लोग पुरानी व्यवस्था को नष्ट करना चाहते थे और नई व्यवस्था का निर्माण करने का

प्रयास कर रहे थे। अतः प्रतिसुधार शक्तिशाली कुलीन वर्ग की ओर से रक्षात्मक तंत्र का प्रयोग कर रहे थे परन्तु जब वे अपनी प्राप्त सुविधाओं का उपभोग कर रहे थे उन्हें इन सबके लिए चुनौतीपूर्ण प्रतिकार का सामना करना पड़ा था। इसे उन्होंने भूमि कानूनों के माध्यम से अपने प्रभावपूर्ण कार्यों को सम्पन्न किया। इस प्रकार के कानूनी उपाय लम्बे-लम्बे प्रावधानों, कानूनी मुहावरों, वाक्यांशों में कहे गए शब्द भार बन कर रह गए थे। जो अनेकार्थी थे और लक्ष्य को प्राप्त करने में अड़चन थे। इन कानूनों को लागू करने में बहुत कठिनाई हुई अथवा यह कह सकते हैं कि इन्हें लागू करना संभव नहीं था। अधिकतर भूमि सम्बंधी सुधार कानून अनुदान सहायता देने का दावा करते थे, किसानों को लाभ पहुँचाने की व्यवस्था करते थे किन्तु किसानों की पैरवी करने के लिए उनका कोई प्रतिनिधि नहीं था और इसीलिए उन्हें तो कोई लाभ नहीं मिला और न ही उनके संगठन बन सके थे।

9.3.1 संरचनात्मक सुधार

लैटिन अमेरिका में संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में देखा गया है कि कृषि सम्बंधी निष्पादन और आय वितरण को भूमि स्वामित्व वितरण से अलग नहीं किया जा सकता था। अतः वे चाहते थे कि औपनिवेशिक द्वारा प्रदत्त दोहरी कृषि संरचना को रोकना और भूमि वितरण को राज्य की प्रतिबद्धता में लाना चाहते थे जो लैटिन अमेरिका के अधिकतर देशों में लागू था। जबकि इन सुधारों का उद्देश्य असमान भूमि काश्तकारी व्यवस्था की समस्या को सुलझाना था जो वास्तव में पूँजीपतियों के विकास में अपना योगदान दे रहे थे।

लैटिन अमेरिका में कृषि सम्बंधी संरचना के विश्लेषण का केन्द्र बिन्दु अब बदल चुका है। कृषि सम्बंधी उत्पादों की माँगों में परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी का प्रस्तुतीकरण और श्रमिकों के वेतन में त्वरित विकास के साथ राजनीति की नीतियों का आधुनिकीकरण किया गया। इन सबसे सम्पूर्ण देश में पूँजीवाद का ही विस्तार हुआ। यह विस्तार परम्परागत भूमिपतियों का रूपांतरण करना था किन्तु गाँवों में नए बुर्जुआ पैदा हो गए। अधिकतर आधारभूत कृषि सम्बंधी सुधार राज्य पूँजीपति संरचना में एकीकृत या संकेन्द्रित हो कर रहे थे।

ये सुधार कृषि उत्पादों में वृद्धि करने में असफल रहे क्योंकि भूमिहीनों, और भूमि-गरीब ग्रामीण परिवारों को पुनःवितरण प्रक्रिया से अलग कर दिया गया था, सामंती सरकारों द्वारा काश्तकारी खेतों को सामूहिक जोत के रूप में लागू कर दिया गया जिससे निवेश की समस्या खड़ी हो गई और व्यक्तिगत किसान नई प्रौद्योगिकी को लागू करने में असमर्थ सिद्ध हुए इसलिए वे जो अपनी इच्छा के अनुसार फसल पैदा करना चाहते थे वे नहीं कर सकते थे। जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सकती थी।

9.3.2 उदारतावादी सुधार

अनेक लैटिन अमेरिकी देशों ने 1990 के दशक में नए उदारतावादी सुधारों को अपनाया। ये सुधार इससे पहले भूमि पर वैयक्तिक निजी सम्पत्ति के अधिकार को शक्तिशाली बनाने के लिए बनाए गए थे, इस दोष में सुधार कर दिया गया और इसके स्थान पर कृषि भूमि और पूँजी के आबंटन के लिए मुख्य तंत्र के रूप में बाज़ार के साथ राज्य को संबद्ध कर दिया गया। यह संरचनात्मक सुधारों के विपरीत था और सुझाव दिया गया था कि बाज़ार स्वामित्व संरचना, भूमि अधिग्रहण तथा कृषि सम्बंधी निष्पादन को कमजोर कर सकेगा। यह संरचना से निष्पादन का संभावित विलगन नवीन-संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रतिपादित किया गया था। और यह भी सुझाव दिया गया था कि कृषि सम्बंधी निष्पादन को उत्तम बनाने की दिशा में अथवा कृषि सम्बंधी उत्पादों को बढ़ाने या वृद्धि करने के लिए अन्य बाज़ार से सम्बंधित घटकों में भी सुधारने के लिए समुचित कदम उठाए गए हैं।

9.4 किसान और भूमि सम्बंधी अधिकार आन्दोलन

जब हम "भूमि अधिकार" आन्दोलनों की चर्चा करते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि कृषक वर्ग के आन्दोलन की भी चर्चा करें। लैटिन अमेरिका में देशज लोगों के आन्दोलन इसके कारण बहुत ही शक्तिशाली रहे हैं। यह आन्दोलन अधिकारों का आन्दोलन है जिसमें - राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। भूमि देशज लोगों के सभी अधिकारों के समक्ष महत्वपूर्ण हो गयी थी, यह भूमि के प्रश्न या अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूम रहा था उसके आसपास चक्कर काट रहा था। जबकि हम कृषक वर्ग की कुछ समस्याओं को छोड़ रहे हैं यह देशज लोगों की समस्याओं के समान ही हैं, उनके विभिन्न परिप्रेक्ष्य में हल करने की आवश्यकता नहीं है जैसे कि उनकी माँगे बिल्कुल ही अलग तरह की हैं। इस इकाई में, हम केवल किसान और कृषि सम्बंधी आन्दोलनों में शामिल मुद्दों पर अपना ध्यान केन्द्रित रखेंगे।

मानव विज्ञानी हॉमबर्ग ने कहा है कि 'दमन की संस्कृति' के रूप में हैसिंटा व्यवस्था में कृषक वर्ग का दमन प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से किया जाता है। रोडोल्फो स्टैवेंहगेन ने बताया है कि कृषक वर्ग हैसिंटा और 'आन्तरिक आन्तरिक उपनिवेशवाद' दोनों में किसान स्वतंत्र रूप से रहता है। यह केवल इसलिए नहीं है कि क्योंकि दोषपूर्ण भूमि संरचना की मौजूदगी के कारण है बल्कि इसका कारण उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के दौरान पूँजीवाद के विस्तार और आर्थिक उदारवाद के कारण यह सब हुआ है।

कृषक वर्ग हिंसा की धमकी के कारण लगातार भयभीत बना रहता है। किसान पूर्व में उसे कुचले या दमित किए जाने से सतत भयभीत रहता है। किसान अपने विकास के प्रति शंकालु और प्रतिरोध में देखा जा सकता है क्योंकि अब उसके दमन का रूप बदल दिया गया है अथवा बदल गया है। यह वास्तविकता तथ्यों से सम्बंधित है क्योंकि वे 'दमन की संस्कृति' में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त किसान वर्ग दमन की संस्कृति के विरोध में खड़ा होता है, तो इसके कई कारण हैं जैसे कि हाल के वर्षों में इस प्रकार की घटनाएँ घटी हैं जिनके कारण किसानों को बल मिला जैसे कि किसान वर्ग में जागरूकता पैदा हुई है, शक्तिशाली और चमत्कारिक नेतृत्व का आविर्भाव, और किसान आन्दोलनों को शहर में हाशिए पर रहने वाले लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त होना है। किसानों द्वारा अपनी विभिन्न माँगों को रखना और विभिन्न प्रकार के साधनों से दबाव बनाकर अपनी माँगों को मनवाना, ये सब अपने आपमें कम महत्वपूर्ण नहीं है। किसानों को आप अतिवादी दृष्टिकोण को अपनाते देख सकते हैं जिसमें नागरिक अवज्ञा यहाँ तक की अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे किसी भी तरह की हिंसा का प्रयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह सब उनके दबाव बनाने के दृष्टिकोणों में शामिल होते हैं।

यहाँ हम इस प्रकार के दो भूमि सम्बंधी अधिकार आन्दोलनों को आपके समक्ष रखेंगे।

9.4.1 मैक्सिको में इमीलियानों ज़पाटा का आन्दोलन

वर्ष 1910-20 के बीच मैक्सिको में हुई क्रान्ति का नेतृत्व इमीलियानो ज़पाटा कर रहे थे जिन्होंने मैक्सिको में कृषक वर्ग के सुधार के लिए कानूनों का निर्माण कराया था। यह क्रान्ति है सिंडास के आस पास हैसिंटाडोस के विरुद्ध संघर्ष था जिन्होंने गाँवों की सामुदायिक मैक्सिको पर जबरन कब्ज़ा कर लिया था और इसके साथ उन गाँव वालों को बलपूर्वक उनके खेतों में काम करने के लिए मज़बूर किया गया था। ज़पाटा ने सबसे पहले इस भूमि को वापस लेने के लिए उसे घेरना आरंभ किया जिसे हैसिंटाडोस ने ग़ैर कानूनी ढंग से बलपूर्वक हासिल किया था।

फ्रांसिस्को माडेरो ने मैक्सिको के उत्तर में राष्ट्रीय विद्रोह की पहली बार गतिविधि आरंभ की जिसका

समर्थन किसान समूहों द्वारा किया जा रहा था। ये किसान समूह तानाशाह पोरफिरियो डायज़ का राष्ट्रपतित्व के पुनः चुनाव को चुनौती दे रहे थे। पोरफिरियो डायज़ के विरुद्ध प्रतिपक्ष का 'दि प्लान डी सैन लुइस पोटोसी' प्रमुख घोषणापत्र था जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों ने बलपूर्वक सामुदायिक भूमि पर गैर-कानूनी कब्ज़ा कर लिया गया है, उसे वापस किया जाए। ज़पाटा मैडेरो के साथ देने को इसलिए सहमत हो गया कि पोरफिरियो डायज़ का तख्ता उलट देने से भूमि से गैर-कानूनी कब्ज़ा हट जाएगा और भूमि सुधार कानून लागू हो जाएँगे, यह आशा लेकर इस संघर्ष में शामिल हुए थे। जब उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली तो ज़पाटा ने संश्रान्त्र विद्रोह आरंभ कर दिया। उन्होंने 1910 के उत्तरार्द्ध में भूमि और स्वतंत्रता की घोषणा के साथ हथियार उठाए थे। उनकी सेना का गठन बागानों और गाँवों के किसानों से भर्ती किए गए हथियारबंद किसानों का संगठन था। उन्होंने बलपूर्वक भूमि पर कब्ज़ा करना आरंभ किया। ज़पाटा मैडेरो उस समय तक सहयोग देता रहा था जब तक वह यह समझता रहा कि भूमि सुधार आन्दोलन को सफलता प्राप्त होगी किन्तु जब उन्हें यह समझ लिया कि भूमि सुधार संबंधी कानून भविष्य में लागू होने वाले नहीं हैं, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने स्वयं की कृषि सम्बंधी कार्यक्रमों का निर्माण किया। इस कार्यक्रम की रूपरेखा 'प्लान डी आयला' (नवम्बर 22, 1911) में प्रस्तुत की गई थी जिसमें गैर-कानूनी भूमि पर कब्ज़े को हटाकर देशज लोगों को वापस कर दी जाए। यह घोषणापत्र भूमि सुधार आन्दोलन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

'प्लान डी आयला' के अनुसार लोगों को अपनी भूमि को वापस लेने के लिए तुरन्त दावे करने चाहिए जिसका गैर-कानूनी रूप से उस पर कब्ज़ा कर लिया था तथा जिस पर वे अभी अपना नाम शीर्षक रखे हुए थे। जिन लोगों को सम्पत्ति हरण के माध्यम से अपनी भूमि को वापस लेने में कठिनाइयाँ आ रही हो उन लोगों को सांझी हैसिंदा भूमि का दो तिहाई क्षतिपूर्ति मुआवजा का भुगतान तुरन्त किया जाए। और जो हैसिंदाडोस इस आन्दोलन का विरोध करेंगे, उनकी सारी भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, इस प्रकार की घोषणा की जाए।

अपनी योजना की सुरक्षा के लिए ज़पाटा लगातार संघीय सरकारों के विरुद्ध युद्धरत रहा था। किसान ज़पाटा की सहायता के लिए रैलियाँ निकालते थे, और 1911 के अंत तक उसने मोरेलॉस पर लगभग नियंत्रण कर लिया था इसके पश्चात् उसने गुरेरो, ओक्साका, पुइबला तथा उस समय के संघीय सरकार के जिले पर अपना नियंत्रण कर अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया था। ज़पाटा की सेना ने 1914-15 के दौरान मैक्सिको नगर पर तीन बार कब्ज़ा किया था। जब कृषि सम्बंधी सुधार से सम्बंधित समझौता उसके जनरल के साथ असफल हो गया, ज़पाटा ने 1914 में 'प्लान डी आयला' को तेज़ी से लागू करने के लिए दबाव बना दिया था। कृषि सम्बंधी सुधारों का महत्वपूर्ण सरकारी नोटिस जारी किया गया जिसमें सरकार ने 1914 में डिक्री जारी की थी।

9.4.2 मोवीमेंटो सेम टेरा (एम एस टी)

हाल के समय में सबसे अधिक किसान आन्दोलन की हड़तालें हुई हैं तो वे वास्तव में निश्चित रूप से मोवीमेंटो सेम टेरा (एम एस टी) के नेतृत्व में लैटिन अमेरिका में हुई या फिर भूमिहीन किसानों का आन्दोलन हुआ था जिसका उदगम स्थान ब्राज़ील रहा है, और अब यह पूरे महाद्वीप में तेज़ी से फैल चुका है। ज़बरन कब्ज़ा करने और भूमि के विशाल क्षेत्रों में कृषि करना तथा विभिन्न लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों में भूमि सुधार के कार्यालयों पर कब्ज़ा करना, उनकी स्थापना करना आदि के लिए एम एस टी ग्रामीण गरीबों के परिवारों के हज़ारों लोगों को अपने साथ मिलाने में सफल रहा है।

एम एस टी कोई राजनीतिक दल नहीं है किन्तु इसके पास एक बहुत बड़ा राजनीतिक बल है, जो वास्तव में एक खुला सत्य है। स्पष्ट है कि इसका मुख्य उद्देश्य भूमि प्राप्त करना और ग्रामीण गरीबों

में इसे पुनः वितरित कर देना है। एम एस टी सामूहिक बन्दोबस्त (*assentamentos*) के व्यापक क्षेत्रों में सहयोग का सर्जन किया गया है। इसे सामूहिकीकरण के आरंभ में या स्वरूप के रूप में सहकारिता सिद्धान्त के आधार पर लागू करना कहते हैं। सम्बंधित प्रदेशों और क्षेत्रों के लोगों की कार्य प्रणाली पर निर्भर कर दिया है। यह मौजूदा और शोषणात्मक सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करने का आवाहन करता है साथ में यह भी घोषणा करता है कि लोगों की भागीदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता पर बल देता है।

एम एस टी की कुछ-कुछ कमजोरियाँ दिखाई देती हैं तथा कहीं-कहीं पर असंगठित संरचना भी दिखाई देती है। फिर भी, इसके स्वास्थ्य और शिक्षा तथा पर्यावरणात्मक ढाँचागत विकल्प जोकि एम एस टी आवाहन करता है, यह स्पष्ट करता है कि इसकी नीतियाँ नवीन-उदारवादी घोषणा से विस्तार के रूप में संभाव्य महान कार्य कहे जा सकते हैं।

अभी हाल ही में, एम एस टी आन्दोलन लैटिन अमेरिका के बहुत बड़े हिस्से में फैल चुका है। बोलीविया में, एक रिपोर्ट के अनुसार भूमिहीनों को भूमि के हजारों एकड़ क्षेत्र के लिए उपयुक्त पाया गया और उसे वितरित कर दिया गया। यह आन्दोलन उस समय आरंभ हुआ जब राष्ट्रपति गोंजालो सेंचेज डी लोज़ाडा ने वायदा किया था कि वह एक वर्ष की अवधि में 500,000 हेक्टेर्स भूमि को भूमिहीनों और ग्रामीण गरीबों में वितरित कर दी जाएगी, परन्तु राष्ट्रपति ऐसा करने में असफल रहे थे। इसके बाद एम एस टी ने बलपूर्वक व्यापक कोलाना सम्पत्ति (राजधानी लापाजा से 80 किलोमीटर दूरी पर है), एम एस टी नेता, एंजेल डुरान ने घोषणा की है कि कम से कम 1800 हेक्टेर्स की 1300 हेक्टेर्स भूमि को भूमि हीनों और ग्रामीण गरीबों को पुनः वितरित कर दी जाएगी। बोलीविया में एम एस टी आन्दोलन राष्ट्र के देशज समुदायों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, व्हे चुआस और आएमारास जिन्होंने 22 करोड़ हेक्टेर्स भूमि की माँग की थी जिसमें कुछ वर्ष पहले सरकार और एम एस टी के बीच समझौता हुआ था जिसका यह भाग अभी तक वितरण करने के लिए चला आ रहा है। बोलीविया में एम एस टी सरकार और ग्रामीण कुलीन के उच्च इंचेलानस् के साथ हिंसात्मक संघर्ष के लिए तेज़ी से तैयारियाँ की जा रही है।

ब्राज़ील में, एम.एस.टी. वर्तमान राष्ट्रपति लुईज़ ईनासिओ 'लुला' डा सिलवा के परिवर्तन के लिए अधीर हो उठा है। अपनी माँगों के लिए दबाव स्वरूप खेतिहर भूमि के लाखों हेक्टेर्स को देने के लिए शामिल किया गया है, एम एस टी ने निजी भूमि पर तथा सम्पत्ति पर कब्ज़ा करने तथा ग्रामीण हड़ताल करने के लिए आयोजन करना आरंभ कर दिया है तथा इसके साथ ही रास्ता रोको या उत्तर और केन्द्रीय ब्राज़ील में पीक्यूटर्स करना आरंभ कर दिया है।

ब्राज़ील में 4 प्रतिशत से भूमिधारी तत्त्वों ने 78 प्रतिशत खेतिहर भूमि पर कब्ज़ा किया हुआ है। (वास्तव में इनमें अधिकतर लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के लोग हैं) इसके लिए एम एस टी ने घोषणा कर दी है कि इसे शीघ्र बदल दिया जाएगा। इसी दौरान, जैसे कि हमने इस रिपोर्ट को फाइल किया है कि सूचना मिली है प्रेंसा लैटिन में एम एस टी ने 100 से अधिक सम्पत्तियों को अपने कब्ज़े में लेलियन है और संतुलन बनाने के लिए अगले सप्ताह में 50 और सम्पत्तियों को अपने कब्ज़े में ले लिया जाएगा। हाल में ही 'लुला' ने एम एस टी से कहा है कि वह थोड़ा शान्त रहे। इसी समय कुछ शक्तिशाली किसानों के गुटों को राजी करने के लिए कहा है कि वे भूमि सुधार को लागू करेंगे परन्तु एम एस टी के नेता गिलमर मोरो की तुरन्त माँग पूरी करने की गति से भूमि सुधार संभव नहीं है।

एम एस टी तेज़ी से अपना धीरज खोती जा रही है, मारो ने यह कहते हुए नोटिस जारी किया है कि यदि सशस्त्र संघर्ष के आयोजन की आवश्यकता पड़ी तो एम एस टी का अगला कदम ब्राज़ील की विशाल भूमि सम्बंधी सम्पत्ति को त्वतरित गति से अपने कब्ज़े में ले लिया जाएगा। इस पर एम एस

टी के अनेक नेताओं के टीओडोरो, सामपेइओ में गिरफ्तार कर लिए गए साउ पालो सम्पत्ति ने एम एस टी संवेदनाओं में आगे और अधिक भड़का दिया है। कोलाम्बिया की एफ ए आर सी ने एक बयान जारी किया है कि वह एम एस टी का समर्थन करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो किसानों की 'सशस्त्र विंग' को लैटिन अमेरिका में भेजा जाएगा।

हाल के सप्ताहों में, एम एस टी ने अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में भूमि के लिए वेनुजुएला ऊरुग्वे, ईकवाडोर में कठोर तथा उग्रवादी संघर्ष छेड़ा है जो केवल भूमि सुधार पर ही केन्द्रित है। एम एस टी के नेताओं के अनुसार लैटिन अमेरिका में आन्दोलन तेज़ी से फैल रहा है, यह महाद्वीप ग्रामीण असंतोष के कारण शीघ्र चूर्ण का पीपा बन कर बैठ जाएगा।

9.5 सारांश

लैटिन अमेरिका में कृषि भूमि सम्बंधी हुए आन्दोलनों का अध्ययन और उन्हें समझने के लिए, यह आवश्यक है कि हमें वहाँ की भूमि संरचना और संस्थाओं का अवलोकन करना पड़ेगा जो औपनिवेशिक समय से ही स्थापित हैं। भूमि अनुदान की व्यवस्था युद्धों में भाग लेने वाले और आक्रमणों के दौरान मारे गए सैनिकों के परिवारों (हैसिंडा/ईनोकोमिंडा व्यवस्था) को भूमि आबंटित की जाती थी। इसके साथ ही अत्यधिक भूमि पर चर्च का स्वामित्व होता था अथवा यह कह सकते हैं कि अधिकतर भूमि पर चर्च का कब्ज़ा होता था। यह परम्परागत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति और इसका प्रकटीकरण अथवा प्रभाव ही लैटिन अमेरिकी देशों की प्रमुख समस्या थी। जबकि कृषि भूमि सुधार करना एजेंडे में मौजूद था परन्तु मामूली या थोड़ी मात्रा में भूमि वितरण करना सभी समस्याओं का उत्तर नहीं था, परन्तु प्रश्न यह बना रहा कि भूमि वितरण सुधार की देश में कृषि विकास की समुचित नीति नहीं थी। कृषि भूमि सुधारों के द्वारा प्रभावी संरचनात्मक परिवर्तन लाने थे। मैक्सिको में कारडेनास के अन्तर्गत 1930 के दशक के भूमि सुधारों, 1980 के दशक में निकारागुआ में सैंडिनिस्ता ने भूमि सुधारों को सम्पन्न किया, इन्होंने जोर देकर कहा था कि राज्य भूमि उत्पादों को संगठित रूप से पुनः वितरित करें। यह संरचनावादी परिप्रेक्ष्य था जिसमें राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अभी हाल में जो भूमि सम्बंधी सुधार हुए हैं, वे प्रकृति में और अधिक उदार हैं तथा भूमि उत्पादों का पुनः वितरण पहले से अधिक बाज़ारमूलक प्रवृत्ति के रहे हैं।

9.6 अभ्यास प्रश्न

- 1) लैटिन अमेरिका में परम्परागत औपनिवेशिक भूमि सम्बंधी संरचना का वर्णन कीजिए।
- 2) क्या आप कह सकते हैं कि लैटिन अमेरिका में किए गए कृषि भूमि सम्बंधी सुधार सफल रहे हैं? क्यों?
- 3) नव-उदार भूमि सम्बंधी सुधारों के असफल होने के क्या कारण रहे हैं? अपना मत प्रकट कीजिए।
- 4) लैटिन अमेरिका में किसानों को लामबंद होने के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा किसान आन्दोलनों का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए।